(ख), और (ग) बाड़मेर तथा चुरू को उद्योग रहित जिलों की सूची में सम्मिलित करने का निर्णय लिया जा चुका है। जालौर मानदंड को पूरा नहीं करता क्योंकि वहां एक मध्यम दर्जे का उद्योग विद्यमान है।

बड़े एककों द्वारा प्रक्षालकों (डिटर्जेंट) आदि का निर्यात

2669. श्री छोटे सिंह यादव :
श्री जगपाल सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बड़े एककों द्वारा निर्मित साबुन प्रक्षालकों (सोप डिटर्जेंट) आदि जैसी वस्तुओं को केवल निर्यात के लिये ही आरक्षित करने और देश में छोटे एककों द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुओं की सप्लाई करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जायेगा और ऐसे बड़े उद्योगों का विवरण क्या है जिनके उत्पादों का निर्यात किया जायेगा और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) इस समय निर्यात की जा रही ऐसी वस्तुओं का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1981-82 से ग्लीसरीन, साबुनों, प्रक्षालकों, सौंदर्य प्रसाधनों तथा स्नान सामग्रियों (टाइलेटरी) के निर्यातों का मूल्य नीचे दिया गया है :—

	*(लाख रुपये)
1981-82	11939.66
1982-83	10351.70
1983-84	2931.50
1984-85(जून 84 तक)	512.30

* संख्याएं अनन्तिम हैं।

Facilities for setting up of industries in Balangir

2670. SHRI NITYANANDA MISHA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Union Government have since issued guidelines for the grant of central assistance to State Governments to take up infrastructural development in identified growth Centres, in no-industry districts;

(b) if so, guidelines suggested by the Union Government to the State Governments; and

(c) specific steps taken for the infrastructural development in the Balangir and other 'No Industry' districts in Orissa ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI PATTABHI RAMA RAO) : (a) Yes, Sir.

(b) The guidelines for Central Assistance for development of infrastructural facilities have been issued on 19-6-1984. Copies of the same are available in the Parliament Library.

(c) State Government has set up Task Forces to identify growth centres and assess infrastructural shortcoming in no-industry districts including Balangir in